*अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में उप गवर्नर का वक्तव्य**

राकेश मोहन

वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार

1. पांच प्रतिशत के आंकड़े को पार करती हुई वृद्धि के साथ विश्व सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) में सतत विस्तार एक नए चरण के उदय की ओर संकेत करता है - एक ऐसा चरण जो अधिक विविधीकृत है और उसमें अधिकांश क्षेत्रों ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है। ध्यान देनेयोग्य प्रेरणास्पद बात यह है कि इस मजबूत चरण को उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से गति मिल रही है तथा इस वैश्विक वृद्धि गति में चीन और भारत का भारी योगदान सतत जारी है। यूरो क्षेत्र में वृद्धि की दर तेज हुई है और जापानी अर्थव्यवस्था में सुधार बरकरार है।

2. नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में दिया गया यह प्रारंभिक आकलन, कि वैश्विक वृद्धि 2006 के लगभग 5.4 प्रतिशत से घटकर 2007 में 4.9 प्रतिशत हो सकती है, इस समय बिल्कुल सही हो सकता है। जबकि हाल ही में बीते समय में डब्ल्यूईओ में वृद्धि के संबंध में किए गए पूर्वानुमान सामान्यतः ऊर्ध्वमुखी संशोधन के साथ एक चक्र से निकलकर दूसरे चक्र में पहुंच गए हैं, तथापि संतोष की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2007 में अनुकूल वृद्धि की संभावनाओं के प्रति जोखिम का स्वरूप नहीं बदला है हालांकि इस चरण में वह शांत दिखाई पड़ रहा है। वहीं, वैश्विक वित्तीय स्थिरता के संबंध में स्थिरता घटने की जोखिमें बढ़ी हैं और अमरीकी आवास बाजार की जोखिमों ने अपना रंग दिखलाना शुरू कर दिया है।

3. सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जिसने जोखिमें घटाने में योगदान दिया है वह है तेल मूल्यों में कमी जो अगस्त 2006 के अपने सर्वोच्च शिखर से नीचे आई। तथापि, तेल मूल्यों में फिर से हाल ही में आ रही तेजी से यह स्पष्ट नहीं है कि यह वृद्धि किस स्तर पर जा कर थमेगी। तेल बाजार के आपूर्ति - मांग संतुलन में कोई मौलिक

* इंटरनेशनल मानेटरी एण्ड फायनांशियल कमिटी के लिए भारतीय शिष्ट मंडल के अगुआ डॉ.राकेश मोहन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 14 अप्रैल 2007 को वाशिंगटन डी.सी. में दिया गया वक्तव्य। यह दल उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका आते हैं।

सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। भू-राजनैतिक जोखिमें भी कम नहीं हुई हैं। यदि तेल मूल्य सतत अस्थिर बने रहते हैं तो वे वृद्धि की संभावनाओं को काफी अस्थिर करेंगे खासकर तेल आयातक विकासशील देशों के लिए।

4. तिस पर भी, तेल मूल्यों के अपने शिखर से नीचे आने का मुद्रास्फीति की संभावनाओं पर तत्काल प्रभाव पड़ा है। उन्नत देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हुई है इसके साथ ही मौद्रिक नीति को कठोर बनाने की तत्काल संभावनाएं धीरे-धीरे समाप्त हुई हैं और इससे वित्तीय बाजारों को कुछ स्थिरता मिली है। तथापि, मौद्रिक नीति की दिशा और कदम के बारे में अभी से पक्का निष्कर्ष निकालना अपरिपक्वता होगी कि यह उन्नत देशों में किस प्रकार आगे बढ़ेगी क्योंकि कोर मुद्रास्फीति का स्तर अभी भी ऊंचा है। उत्पादन वृद्धि में सूचित मंदी और उत्पादन अंतर के घटने के साथ उन्नत देशों में मुद्रास्फीतिगत चिंताएं अभी भी मौजूद हो सकती हैं। बहुत से उभरते बाज़ार अभी भी मुद्रास्फीति के दबावों को झेल रहे हैं और उन्होंने अपनी मौद्रिक नीति कठोर कर दी है। यदि तेल के मूल्य अस्थिर हो जाते हैं तो मुद्रास्फीति की चिंताएं फिर से अपना सिर उठा सकती हैं।

5. चिंता का एक अन्य क्षेत्र है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमरीकी मंदी का प्रभाव। मौजूदा मंदी आवास क्षेत्र के सब प्राइम खंड में विपरीत परिस्थितियों के चलते शुरू हुई है। शेयर बाज़ार की हाल की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह असंभव नहीं लगता कि सब प्राइम सेक्टर की यह समस्या आवास क्षेत्र के अन्य खंडों में व्याप्त हो जाए। ऐसे परिदृश्य में उपभोग मांग, जो कि अब तक स्थिर रही है, प्रभावित हो सकती है।

6. वैश्विक असंतुलनों का चिर स्थायी बने रहना लगातार चिंता का विषय बन गया है। ऐसी संभावना है कि डालर के मूल्य में गिरावट और इससे जुड़ी अमरीकी वृद्धि में मंदी चालू खाता घाटा के क्षरण को नियंत्रित रखने की कोशिश करेगी तथापि, सर्वाधिक अनुकूल परिदृश्य में भी अमरीका की निवल विदेशी देयताओं की स्थिति में और गिरावट का क्रम जारी रहेगा जो अंतिम समायोजन की संभावनाओं को बढ़ाता है।

7. वैश्विक उत्पादन की धारा में चीन और भारत के बढ़ते एकीकरण ने वैश्विक उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता काफी बदल दी है। हालांकि विनिमय दरों में होनेवाले ये परिवर्तन समायोजन की इस प्रक्रिया का एक अंग हैं लेकिन ऐसे असंतुलनों में महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ियों की घरेलू नीतियों में परिवर्तन के माध्यम से ही ये अधिकांश समायोजन होंगे। इसमें अमरीका और भारी आधिक्य (सरप्लस) वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच बचत-निवेश व्यवहार के पुनः संतुलन का समावेश होगा। यदि ये समायोजन मुख्यत: विनिमय दर समायोजन के माध्यम से होते हैं तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए इसका व्यापक प्रशाखन होगा। उभरते बाजार वाले देश इसके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहेंगे क्योंकि उनकी बाह्य देयताओं का प्रमुख हिस्सा अमरीकी डालर में है। हालांकि वैश्विक असंतुलनों का अनियंत्रित रूप से खुलना एक कम संभावना वाली घटना है लेकिन ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मुख्य पणधारियों द्वारा संगठित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

8. हालांकि अमरीकी वृद्धि के मंद हो जाने की संभावना है, सुदृढ़ राजकोषीय निष्पादन को अर्थव्यवस्था की नमनीयता बढ़ानी चाहिए। तेज मंदी की स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि इस मंदी को यूरो क्षेत्र और जापान द्वारा समेट लिया जाए ताकि वैश्विक वृद्धि में उछाल बना रहे। वृद्धि संबंधी अनुमान दर्शाते हैं कि यूरो क्षेत्र की वृद्धि लौटकर अपनी क्षमता के स्तर पर आ जाएगी जोकि तुलनात्मक रूप से निम्न रहती है। निष्पादन के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि स्पर्धा बढ़ाकर तथा श्रम बाजार की विसंगतियों को दूर करके इस क्षेत्र और अमरीका के बीच के उत्पादकता

अंतर को घटाया जाए। हालांकि जापान में वृद्धि के आवेग में स्पष्टतः वृद्धि दिखाई दे रही है लेकिन राजकोषीय सुधार और आपूर्ति पक्ष संबंधी ढांचागत सुधार जरूरी हैं ताकि व्यापारेतर क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

9. ईंधन और ईंधन से इतर वस्तुओं के ऊँचे मूल्यों से उत्पन्न होने वाले व्यापार आघातों के सतत बने रहने से अनेक देशों को फायदा हुआ है। हालांकि वस्तुओं की कीमतों में उछाल बने रहने की आशा है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रत्याशा से ज्यादा तेज मंदी होने से संवेदनशीलता बढ़ेगी, विशेषकर अफ्रीका के अल्प आय वाले देशों में। अफ्रीका को भी ऋण राहत तथा समष्टि आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ बनाने के सतत प्रयासों से लाभ हुआ है। उभरते यूरोप में वृद्धि बढ़ी है लेकिन चालू खाता संतुलन की खराब होती स्थिति के चलते संवेदनशीलता भी बढ़ी है। जबकि मध्य पूर्व के देश सुदृढ़ वृद्धि का आनंद उठा रहे हैं, तेल के मूल्यों में कमी के साथ ही क्षेत्र के लिए चालू खाता अधिशेष का स्तर घट जाने की आशा है और इसके चलते व्यय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगी।

10. हाल के वर्षों में, अनुकूल वित्तीय बाजार स्थितियां वैश्विक वृद्धि का समर्थनकारी रही हैं। तथापि, वित्तीय बाजारों में अंतर्निहित जोखिमें बढ़ गई हैं। बाजार भी पहले से ज्यादा विवेकी हो गए हैं। बाजार इकाइयों की लीवरेज स्थितियां बढ़ी हैं जैसा कि लीवरेज खरीदारी (एलबीओ) में परिलक्षित है। जोखिम (हेज) निधियों की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। तथापि, जोखिम निधियों के परिचालनों में पारदर्शिता की कमी के चलते जोखिमों का ठीक-ठीक आकलन कठिन हो जाता है। कैरी ट्रेड के सतत बने रहने ने भी वित्तीय बाजारों में जोखिमों को और भी प्रबल कर दिया है।

11. वित्तीय वैश्वीकरण के साथ ही परिपक्व बाजारों में जोखिमभरी वित्तीय आस्तियों के प्रति उभरते बाजारों का एक्सपोज़र बढ़ा है । इसी प्रकार, संस्थागत निवेशकों की जोखिम उठाने की भूख भी ज्यादा प्रतिलाभ कमाने की खोज में बढ़ी है। यह उभरते बाजार वित्तीयन के लिए स्प्रेड को दबाने के रूप में परिलक्षित हो रही है और इसे मूलतत्वों में सुधार द्वारा पूर्णत: उचित नहीं ठहराया जा सकता । समग्र रूप में जैसा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वित्तीय जोखिमें बढ़ी हैं। जोखिम लेने की भूख के घटने और परिणामतः लीवरेज स्थितियों के खुलने की स्थिति में उभरते बाजारों में गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं।

12. वित्तीय वैश्वीकरण के साथ ही उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ऊंचे प्रतिलाभ से फायदा उठाने के मौके खोजने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा विदेश से किए जाने वाले भारी अंतर्वाहों से उत्पन्न जोखिमों का खतरा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों पर बढ़ा है। भारी पूंजी प्रवाहों के साथ बहुत से उभरते बाजार और विकासशील देश समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों को स्थिर बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। प्राधिकारियों को भारी पूंजी प्रवाहों से वित्तीय बाजारों में उत्पन्न होने वाली अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए निधियों के निष्प्रभावीकरण और मौद्रिक नीति को कठोर बनाने की गतिविधियों में लगना पड़ रहा है। तथापि, इस संबंध में हुए अनुभव अपनी कठिनाइयां बयां करते हैं। उदाहरण के लिए, ब्याज दर बढ़ाकर मौद्रिक नीति कठोर करने से और पूंजी अंतर्वाह हो सकता है और इसके लिए और भी ज्यादा निधियों को निष्प्रभावी करना होगा। इस प्रकार, प्राधिकारी अपने देशों में उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो भारी विदेशी प्रवाहों और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता, जोकि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा की गई संभावित अनुचित जोखिम मूल्यन से संबद्ध है, से उत्पन्न हो रही हैं।

13. कुल मिलाकर मुझे वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही हैं। कच्चे तेल के मूल्यों

के व्यवहार, अमरीकी आवास बाजार में विपरीत गतिविधियों, वैश्विक असंतुलन के बने रहने, वित्तीय बाजारों में अत्यधिक लीवरेज स्थितियों और मुद्रास्फीतिकारी दबावों के संभावित उदय से उत्पन्न होनेवाली अनेक जोखिम हैं। इसके अलावा, वैश्विक वृद्धि पर पड़ने वाले विपरीत परिणामों सहित संरक्षणवादियों के दबावों का खतरा भी है। उभरती स्थितियों पर एक पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है, साथ ही नीति निर्माताओं को उभरती चुनौतियों के प्रति त्वरित और कारगर प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए।

चौकसी को नया रूप प्रदान करना

14. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (कोष) का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व चौकसी है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हो रहे सतत कार्य को हमने नोट किया है। हम उन प्रयासों को समर्थन देंगे जो चौकसी की प्रासंगिकता का संवर्धन करेंगे और कारगरता बढ़ाएंगे। प्रबंध निदेशक द्वारा आगे बढ़ने के लिए मौलिक दृष्टिकोण और सिद्धांत स्पष्टतः और सारगर्भित रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं : (i) संशोधित निर्णय को सर्वाधिक व्यापक संभावित समर्थन बटोरना चाहिए; (ii) इससे किसी भी प्रकार नई बाध्यताएं प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः शुरू नहीं होनी चाहिए और (iii) इसे पहले से ज्यादा अनुपालन आधारित दृष्टिकोण की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर इस मामले में दृष्टिकोण अपनाएं तो यह कोष के सदस्यों की तमाम आशंकाओं को शांत कर देगा।

15. 1977 के निर्णय की समीक्षा के संदर्भ में मैं यह समझता हूँ कि इस निर्णय का कानूनी आधार सदस्यों की विनिमय दर व्यवस्था संबंधी चौकसी विषयक आर्टिकल IV सेक्शन 3(बी) से मिलता है। नए सिद्धांतों, जिन पर कि वर्तमान में चर्चा हो रही है, का अंगीकरण विनिमय दरों की चौकसी के विषय तक ही सीमित रहना चाहिए। विनिमय दर प्रबंधन पर बाह्य परिणाम डालने वाली हमारी देशी नीतियों को विशेषित करनेवाले ऐसे किसी नए सिद्धांत को जुड़ते हुए देखकर हमें तकलीफ होगी। हालांकि कोष के लिए यह मार्ग खुला है कि वह विचार हेतु ऐसे 'कारक' या 'विचार बिंदु' सुझाए जोकि सुदृढ़ मौद्रिक, राजकोषीय अथवा वित्तीय क्षेत्र की नीतियां बनाते हैं' यह बात एकदम साफ तौर पर समझी जानी चाहिए कि ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत आर्टिकल IV सेक्शन 3(ए) के अंतर्गत कोष के सदस्यों की घरेलू नीतियों के संबंध में कोष के पर्यवेक्षण को योग्य ठहराते हैं। वे आर्टिकल IV सेक्शन 3(बी) के अंतर्गत विनिमय दर पर कड़ी चौकसी के योग्य सिद्धांतों के रूप में न तो माने जा सकते हैं और न माने जाने चाहिए।

16. जहां तक विनिमय दर संबंधी चौकसी की बात है 'विनिमय दर के मौलिक बेमेल संबंध' की अवधारणा को औपचारिक रूप से स्वीकार करने में प्रस्तावित नए सिद्धांत का प्रारूप आर्टिकल IV के उद्देश्य से आगे जाते हुए जान पड़ता है। अवधारणात्मक और प्रणालीबद्ध अनिश्चितताओं को देखते हुए औपचारिक निर्णय में 'विनिमय दर के बेमेल संबंध' नामक पारिभाषिक शब्द को शामिल करना ठीक नहीं होगा। यह तथ्य कि वैकल्पिक दृष्टिकोण से 'विनिमय दर के बेमेल संबंध' के व्यापक रूप से भिन्न अनुमान मिलते हैं अतः ऐसे विनिमय दर आकलनों पर नीतिगत सलाह को बांधना उचित नहीं होगा। तथापि, उभरते बाजारों के लिए विनिमय दरों की संवेदनशीलता को देखते हुए विनिमय दर मूल्यांकन को अंदर ही रखने के लिए एक विश्वसनीय परामर्शदाता के रूप में कोष की भूमिका की भावना वांछनीय है।

17. विप्रेषण, स्वतंत्रता और जिम्मेवारी ढांचे के संबंध में हुई चर्चाओं के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं: (i) अधिकाधिक प्राथमिकता देने के साथ चौकसी के फोकस को सुधारना और (ii) चौकसी की कारगरता का मूल्यांकन करने के लिए पद्धति में सुधार लाना। हम चौकसी समीक्षाओं और प्राथमिकताकरण के पद्धति विषयक पहलुओं को मजबूत

बनाने के पक्ष में हैं। तथापि, इस पर बड़ी सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या केवल इस प्रयोजन हेतु एक नया नीतिगत वक्तव्य जारी करने से कोई मूल्यवर्धन होगा ? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि त्रि-वर्षीय चौकसी समीक्षाओं के माध्यम से चौकसी के उद्देश्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाए। मुझे विश्वास है कि बोर्ड दोनों ही तरीकों के फायदे-नुकसान पर गौर करते हुए एक व्यापक सहमति के प्रस्ताव के साथ सामने आएगा।

18. मैं द्विपक्षीय चौकसी में कोष के अधिदेश के मुख्य क्षेत्रों पर जोर देने का स्वागत करता हूँ। देशों के बीच बिखरे चौकसी के तरीकों पर अपेक्षाकृत ज्यादा फोकस के साथ बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय चौकसी के बीच बेहतर समन्वय रखने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है। उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच विश्वास, जोकि चौकसी को कारगर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, का माहौल बनाने के उद्देश्य से एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है।

कोटा और स्वर

19. मैं बोर्ड में कोष के शासन संबंधी इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर होने वाली चर्चाओं को नोट करता हूँ। पहले राउंड में की गई तदर्थ कोटा वृद्धियों के बाद यह महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक समयबद्ध ढंग के साथ द्वितीय चक्र में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का पक्का इरादा दर्शाए। इस संबंध में वचनबद्धता सिंगापुर प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से निहित है। मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि मौजूदा वैश्विक वास्तविकता को पूरा करने के लिए कोटा फार्मूला फिर से विधिवत बनाया (अलाइन किया) जाए। यह मौलिक सुधार कम प्रतिनिधित्व वाले देशों को अधिक हिस्सा देकर लाया जाना चाहिए जब कि जिन देशों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है उन्हें थोड़ा पीछे रखने की आवश्यकता है।

20. आज की चुनौती यह है कि यह सुधार एक नए, सरल, पारदर्शी, सरल और रैखिक कोटा फामूर्ला के जरिए लाया जाए। हमें विश्वास है कि यदि हम एक नए कोटा फार्मूला की दिशा में काम करें जिससे हमें दो परिणाम प्राप्त हों तो यह संभव है। पहला, फार्मूला ऐसा होना चाहिए ताकि वैश्विक रूप से जो आर्थिक परिवर्तन हुए हैं उनको रखते हुए कोटा शेयरों का पुनः संतुलन हो। दूसरी और उतनी ही महत्त्वपूर्ण बात है उद्देश्य, जिसके तहत निम्न आय वाले देशों के कोटे का हिस्सा यथासंभव पूरी तरह से संरक्षित किया जाए। हम पाते हैं कि ये जुड़वां परिणाम केवल तभी प्राप्त हो सकते हैं जब सैद्धांतिक रूप से नए फार्मूले में सकल घरेलू उत्पाद की गणना पूरी तरह से क्रय शक्ति समता के आधार पर की जाए। क्रय शक्ति समता पर सकल घरेलू उत्पाद के साथ बाजार विनिमय दर पर सकल घरेलू उत्पाद के मिश्रण के आधे मन से किये गए कार्य से ये जुड़वां उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। इसके अलावा, एक ही मुद्रा वाले देशों के संदर्भ में कोटे की गणना में खुलेपन के चर (वैरिएबल) की नीर-क्षीर संवीक्षा आवश्यक है। हमारा मत है कि व्यापक सुधारों के लिए हमारा प्रस्ताव मात्र ही विकासशील देशों के लिए पर्याप्त, न्याय संगत और उचित प्रतिनिधित्व दिला सकेगा। विकासशील देशों के ऐसे व्यापक प्रतिनिधित्व से कोष के कार्यक्रमों और नीतियों की स्वीकार्यता, स्वामित्व और प्रभावशालिता का संवर्धन होगा।

21. इस जुड़वां परिणाम वाले दृष्टिकोण के लिए सभी सदस्य देशों की ओर से परिणामवादी भाव और समझौते की भावना जरूरी है। तथापि, हम इस बात से निराश हैं कि इस दृष्टिकोण के ठीक विपरीत कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जा रहे हैं जो इस सुधार प्रक्रिया की भावना और प्रयोजन को कम करते हैं। यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि सुधार के उद्देश्य कई तरीकों से पूरे किए जा सकते हैं। हमारी दृष्टि में, अनेक तरीकों का वायदा एक परेशान करने वाली मरीचिका है। इसका तरीका केवल एक है और वह

यह है कि एक फार्मूला बनाया जाए जो वास्तविक कोटे को वर्तमान वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाए। एक अन्य सुझाव यह रहा है कि वास्तविक कोटे के बजाय वर्तमान परिकलित कोटा के संशोधित संस्करण को बेंचमार्क किया जाए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किए गए सुधारों से बाहरी विश्व और हम समझते हैं कि यह एक ऐसा परिणाम है जो वास्तविक कोटों को वर्तमान वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना चाहता है। हमें इस उद्देश्य को धूमिल करने के सभी प्रयासों का विरोध करना चाहिए।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और संकट निवारण

22. अनवरत सुधारों और सुदृढ़ नीतिगत ढांचों से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की नमनीयता बढ़ी है। अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने स्व-बीमा तैयार किया है और उन्हें पहले से ज्यादा बाजार विश्वास मिला हुआ है। वहीं ये अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक पूंजी प्रवाहों में बाह्य परिवर्तनों से उत्पन्न होनेवाली अनेक नीतिगत चुनौतियों का समय-समय पर सामना कर रही हैं। अतएव, कोष को इन देशों के साथ अपने इंटरफेस को अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि वह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वे उभरते बाजारों की एक खास तरह की वित्तीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने टूल किट को सुदृढ़ बनाएं ।

23. इस संदर्भ में, नए चलनिधि लिखत की डिजाइन के संबंध में हो रही नियमित चर्चाओं पर मैंने विचार किया है। हम नए चलनिधि लिखत में आकस्मिक स्वरूप का गुण देखते हैं जो कोष के संकट निवारक उपायों को दृढ़ता प्रदान करेगा। यह महत्त्वपूर्ण है कि नई लिखत प्रस्तावित योग्यता मानदंड और अन्य रूपात्मकताओं के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के पश्चात ही बनाई जाए ताकि संभावित सदस्य देश इसके संभावित उपयोग के बारे में आश्वस्त रहें।

निम्न आय वाले देशों में भूमिका

24. कोष को अपने निम्न आय वाले सदस्य देशों की सहायता करने के बहु-पक्षीय प्रयासों में पूरी तरह से लगे रहना चाहिए ताकि वे सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकें और अपनी समर्थनकारी नीतियों से ऋण वहनीयता सुनिश्चित करने के मामलों को सुलझा सकें। उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में कोष की भूमिका पर स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की रिपोर्ट की सिफारिशें और कोष-बैंक सहयोग पर मालन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें कम आय वाले देशों में कोष की और कारगर भूमिका के लिए अवसर उपलब्ध करती हैं।

समर्थ संस्था का प्रबंधन

25. कोष के वहनीय वित्तपोषण के संबंध में प्रख्यात व्यक्तियों की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह रिपोर्ट समय पर आई है और वर्तमान वित्तपोषक मॉडल की कमजोरियों को दूर करने के लिए एक सुदृढ़ ढांचा उपलब्ध कराती है। व्यय ढांचे के साथ इस रिपोर्ट पर और चर्चाएं कराए जाने की आवश्यकता है। इस समिति की कुछ सिफारिशें जिनमें कोटा से बाहर निवेश करने और स्वर्ण का कुछ हिस्सा बेचने के प्रस्ताव शामिल हैं, दूरगामी हैं और इन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। तकनीकी सहायता के लिए शुल्क वसूलने के प्रस्ताव से अनेक जरूरतमंद देशों में इसका उपयोग हतोत्साहित होगा और इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम कोष के लिए एक दक्ष, न्यायपूर्ण और वहनीय आय मॉडल की दिशा में कार्य करने की आशा करते हैं जो इसकी मध्यावधि नीति के अनुरूप होगा।

क्षेत्र की गतिविधियां

26. अब मैं अपने क्षेत्र में हो रही गतिविधियों के कुछ पहलुओं का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। **भारत** में विगत दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 9 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई और 2007-08 के लिए संभावनाएं लगातार अनुकूल बनी हुई हैं। बचत और निवेश दरों में काफी वृद्धि हुई है और इससे सतत उच्च वृद्धि की संभावनाओं में दृढ़ता आई है। कारोबार विश्वास ऊंचा बना हुआ है। कुछ स्फीतिकारी दबाव उभरे हैं जो मांग कारकों और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं, दोनों को दर्शाते हैं। हमने राजकोषीय, मौद्रिक और आपूर्ति पक्षों के संबंध में अनेक उपाय किए हैं जिससे 2006-07 के लिए मुद्रा स्फीति की दर 5.5 प्रतिशत के आस-पास स्वीकार्य सीमा में बनी रहने की आशा है। चालू खाता की स्थिति नियंत्रणीय है और उसे सुदृढ़ निर्यातों और अदृश्य प्राप्तियों तथा पूंजी प्रवाहों से सहारा मिला। 2006-07 में राजकोषीय निष्पादन विगत वर्ष की तुलना में बेहतर रहा और 2007-08 के लिए बजट का लक्ष्य राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून के उद्देश्य के अनुरूप राजकोषीय समेकन के पथ पर अग्रसर रहना है। हम आर्थिक सुधारों, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता के प्रति वचनबद्ध हैं।

27. बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था निर्धनता कम करने और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को पूरा करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति करते हुए स्थिर वृद्धि बनाए रखने और मुद्रास्फीति को संतुलित रखने के मार्ग पर सतत अग्रसर है। निर्धनता कटौती और वृद्धि सुविधा (पीआर जीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत कोष की सफलता के दृष्टांतस्वरूप बांग्लादेश को चुना जा सकता है। कारोबारी वातावरण में इंद्रियगोचर सुधार हुआ है जैसा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) के सतत प्रवाह में परिलक्षित है। प्राधिकारियों की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की अगुवाई मोटे तौर पर सटीक रही है जैसा कि समग्र राजकोषीय घाटे में तथा चालू खाता घाटे के आकार में आई गिरावट से स्पष्ट है।

28. **श्रीलंका** की अर्थव्यवस्था ने सकल घरेलू उत्पाद में 2005 की 6 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर 2006 में 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की। 2007 के लिए दृष्टिकोण मजबूत रहा। बेरोजगारी घटकर 6.5 प्रतिशत तक आ गई। स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति में कठोरता लाई गई है। सुनामी के कारण विध्वंस से हुए नुकसान की वजह से पुनर्निर्माण पर किए गए व्यय के बावजूद राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखा गया है। भुगतान संतुलन इस समय अधिशेष की स्थिति में है। सरकार ने व्यापक आधार वाली सहभागिता और आबादी के सभी वर्गों को लाभ का न्यायसंगत वितरण करने के साथ एक सुदृढ़ और स्थिर अर्थव्यवस्था सृजित करने के लिए ''महिंदा चिंतना - विज़न फार ए न्यू श्री लंका - ए टेन ईयर होराइज़न 2006-16'' में आर्थिक नीतिगत ढांचे का उल्लेख किया है।

29. **भूटानी** अर्थव्यवस्था ताल पनबिजली परियोजना के प्रारंभ होने के साथ ही और ज्यादा वहनीय आधार पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। जुलाई 2006 में ताल परियोजना के शुरू होते ही 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 14 प्रतिशत तक बढ़ जाने की प्रत्याशा है। चालू खाता में और सुधार आने की आशा है तथा लोक ऋण में भी काफी कमी आने की संभावना है। संभावित स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रण में रखने के लिए मौद्रिक नीति सटीक बनी हुई है।